हिन्दी साप्ताहिक

R.N.I. No. UPHIN/2022/83621

जनता का सच

वर्ष 05 अंक 38 | लखनऊ | शनिवार 26 सितम्बर 2026 | पृष्ठ 04 मूल्य 2 रूपया

संक्षिप्त समाचार

खाने के तेल पर बड़ी राहत, सरकार ने घटाई कस्टम ड्यूटी

एजेंसी

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन के बीच केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों को लेकर ऐसा फैसला किया है, जिससे आने वाले दिनों में आम उपभोक्ताओं को रसोई के बजट में राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेलों पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी में कटौती कर दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक नई दरें 24 सितंबर 2026 से लागू होंगी। नए बदलाव के तहत कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे पाम तेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। वहीं कच्चे सूरजमुखी तेल पर लगने वाली 10 फीसदी ड्यूटी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले का सीधा असर खाद्य तेलों की आयात लागत पर पड़ने की उम्मीद है। भारत अपनी घरेलू जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों और आयात शुल्क में होने वाले बदलाव का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ता है। हालांकि, कस्टम ड्यूटी घटने का पूरा लाभ खुदरा ग्राहकों तक कितनी जल्दी और कितनी मात्रा में पहुंचेगा, यह अंतरराष्ट्रीय कीमतों, रुपये की विनिमय दर, आयात लागत, स्टॉक और बाजार की प्रतिस्पर्धा जैसे कई कारकों पर निर्भर करेगा। भारत सरकार का खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भी खाद्य तेलों की आयात शुल्क संरचना की समय-समय पर समीक्षा करता है। सरकार के नए फैसले का सबसे प्रमुख असर कच्चे सोयाबीन और पाम तेल पर पड़ा है। दोनों तेलों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पहले 10 फीसदी थी, जिसे घटाकर अब 5 फीसदी कर दिया गया है। यानी इन दोनों कच्चे खाद्य तेलों के आयात पर लगने वाला मूल सीमा शुल्क आधा हो गया है। सोयाबीन और पाम तेल भारतीय खाद्य तेल बाजार में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। इनका उपयोग घरों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में भी होता है। ऐसे में आयात लागत कम होने पर तेल कारोबारियों और रिफाइनरियों की लागत पर इसका असर पड़ सकता है।

बाजार में पर्याप्त आपूर्ति और अन्य लागत स्थिर रहने की स्थिति में इसका कुछ हिस्सा उपभोक्ताओं तक भी पहुंच सकता है। सरकार ने कच्चे सूरजमुखी तेल के मामले में और बड़ी कटौती की है। पहले इस पर 10 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती थी, जिसे अब घटाकर शून्य कर दिया गया है। यानी कच्चे सूरजमुखी तेल के आयात पर अब बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। सूरजमुखी तेल की कीमतों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि खुदरा बाजार में कीमतों में वास्तविक कमी कितनी होगी, यह केवल कस्टम ड्यूटी से तय नहीं होगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सूरजमुखी तेल के भाव, आयातकों की लागत, परिवहन और रिफाइनिंग खर्च सहित कई दूसरे घटक भी अंतिम कीमत तय करते हैं। सरकार ने केवल कच्चे तेलों की ड्यूटी नहीं घटाई है, बल्कि रिफाइंड खाद्य तेलों पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी कम की गई है। रिफाइंड सोयाबीन और रिफाइंड पाम तेल पर शुल्क 32.5 फीसदी से घटाकर 27.5 फीसदी कर दिया गया है। इसी तरह रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 32.5 फीसदी से घटाकर 22.5 फीसदी की गई है। इस तरह सरकार ने कच्चे और रिफाइंड दोनों श्रेणियों में शुल्क संरचना में बदलाव किया है। इसका उद्देश्य आयातित खाद्य तेलों की लागत को कम करना है।

पीएम मोदी का चिंतन शिविर ● कैबिनेट मंत्रियों संग प्रधानमंत्री की बैठक

इनोवेशन लैब की तरह काम कर रही सरकार : पीएम मोदी

❖अनुभव और स्वतः सुखाय जैसी पहलों से बदला शासन का ढांचा।

एजेंसी



नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ %चिंतन शिविर% आयोजित किया। इस मौके पर एक्स अकाउंट %मोदी स्टोरी% ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने शासन-प्रशासन के कामकाज के तरीके में कई ऐसे प्रयोग किए हैं, जिन्होंने सरकारी व्यवस्था को नई दिशा दी है। मोदी स्टोरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, ÷सुना है कि आज प्रधानमंत्री मोदी अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ चिंतन शिविर कर रहे हैं? वर्षों से उन्होंने सरकार के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है और अक्सर शासन को एक %इनोवेशन लैब% की तरह देखा है।÷

पोस्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐसे प्रयोग शुरू किए, जिनमें कुछ बेहद सरल हैं तो कुछ दूरगामी प्रभाव वाले। इनमें से एक पहल %अनुभव% है, जिसके तहत सेवानिवृत्त होने वाले वरिष्ठ अधिकारी अपनी सेवा के दौरान हासिल अनुभवों और सीख को दस्तावेज के रूप में दर्ज करते हैं, ताकि अगली पीढ़ी के अधिकारी उससे लाभ उठा सकें। मोदी स्टोरी ने %स्वतः सुखाय% पहल का भी उल्लेख किया। इसके तहत अधिकारी अपने विभाग से अलग किसी सार्वजनिक हित के प्रोजेक्ट पर स्वेच्छा से काम करते हैं, जिससे उन्हें समाज के लिए योगदान देने का संतोष मिलता है। पोस्ट के अनुसार %बैक टू द फर्स्ट पोस्टिंग% पहल में वरिष्ठ अधिकारियों को अपने प्रशासनिक करियर की पहली तैनाती वाले जिले या तालुका में वर्षों बाद वापस जाकर यह देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वहां कितना विकास हुआ है। इसके अलावा %असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम% का भी जिक्र किया गया, जिसके तहत नए नियुक्त आईएएस अधिकारियों को पहली फील्ड पोस्टिंग से पहले तीन महीने तक केंद्र सरकार के मंत्रालयों में काम करने का अवसर दिया जाता है, ताकि वे केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली को करीब से समझ सकें। पोस्ट में %वन सेक्रेटरी, वन तालुका% पहल को भी रेखांकित किया गया। इसके तहत वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को पिछड़े तालुकों की जिम्मेदारी दी जाती है, ताकि वे जमीनी हकीकत से जुड़े रहें और विकास कार्यों की निगरानी कर सकें। मोदी स्टोरी ने इन पहलों को नौकरशाही और शासन व्यवस्था में किए गए ऐसे प्रयोग बताया, जिनका उद्देश्य प्रशासन को अधिक प्रभावी, अनुभव-आधारित और जमीनी जरूरतों से जुड़ा बनाना है।

राज्य मंत्रियों के दूसरे समूह से संवाद

चिंतन शिविर के बीच प्रधानमंत्री राज्य मंत्रियों के दूसरे समूह से 28 फरवरी को संवाद करेंगे। इस दौरान मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा होगी और अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री राज्य मंत्रियों की राय लेने के साथ कुछ दिशा निर्देश जारी करेंगे। पीएम 20 राज्य मंत्रियों के एक समूह से सात सितंबर को समीक्षा बैठक कर चुके हैं।

ऐसे चलेगा कार्यक्रम

चार दिन के शिविर के लिए चार थीम तय किए गए हैं। पहले दिन का थीम व्यक्तित्व विकास के जरिये स्व विकास, दूसरे दिन का जनविश्वास से जनाधार, तीसरे दिन (30 सितंबर) का विभागीय सफलता और अंतिम दिन का थीम प्रभावी संवाद होगा।

यह है खास मकसद

इससे पहले पीएम मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2015 में चिंतन शिविर के जरिए कामकाज में तेजी लाने, पारदर्शिता बढ़ाने के टिप्स दिए थे। तब उन्होंने नए मंत्रियों को गवर्नेंस का गुर सिखाया था। इस बार की बैठक का मकसद लोगों को मोदी में आए सकारात्मक बदलावों पर लोगों से प्रभावी संवाद करने, लोगों के सरकार के कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों सरकार के प्रति विश्वास को कायम रखते हुए इसे जनाधार में बदलने का तरीका सिखाने के लिए है।

आयुष्मान भारत PM-JAY के 8 साल पूरे

एजेंसी



नई दिल्ली। केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने बुधवार (23 सितंबर) 8 साल पूरे कर लिए हैं. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने इस योजना की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि इसका मकसद देश के हर नागरिक तक सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है. पीएम ने कहा कि इससे देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक की हेल्थ कवरेज मिली है, जो कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थकेयर स्कीम बनाती हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए देश के सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी. पीएम ने इस योजना ने देश के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को अस्पताल के भारी खर्च से मुक्ति दिलाई है और स्वास्थ्य सेवाओं को हर घर के दरवाजे तक पहुंचाया है। अपनी पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा 'आठ साल पहले, आयुष्मान भारत की शुरुआत इस सोच के साथ की गई थी कि हर भारतीय को बेहतरीन और किफायती हेल्थकेयर मिल सके. आज, 60 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को सालाना 5 लाख रुपये का हेल्थ कवर मिल रहा है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम बन गई है'।

राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला

वोटों की चोरी देशद्रोह, वक्त आने पर बख्शेंगे नहीं

एजेंसी



नई दिल्ली। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चल रहे विवाद के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) और चुनाव अधिकारियों पर गड़बड़ी का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि ÷समय आएगा, हम आपको बख्शेंगे नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने कहा, ÷वोट की चोरी भारत के लोगों के खिलाफ एक अपराध है और हमारे संविधान पर सीधा हमला है। इसे अंजाम देने वाले भाजपा, आरएसएस और चुनाव आयोग ने देशद्रोह का काम किया है। इंसाफ जरूर होगा। गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा, ÷मैं चुनाव आयोग और चुनाव अधिकारियों से साफ कह रहा हूं। आप जो कर रहे हैं, वह गलत है। उन्होंने कहा, यह देशद्रोह है। समय आएगा! हम आपको पकड़ेंगे, आप बच नहीं पाएंगे। यह ताजा विवाद एक प्रमुख अखबार की रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 10 महीनों के दौरान 14 मौकों पर दो चुनाव आयुक्तों ने आयोग के फैसलों पर आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताई थी। रिपोर्ट के अनुसार, ये आपत्तियां कई तरह के फैसलों और प्रक्रियाओं से जुड़ी थीं। इनमें यह आरोप भी शामिल था कि नए वोटरों को जोड़ने और वोटर लिस्ट से नाम हटाने से जुड़े कुछ मामलों और मुद्दों के बारे में आयुक्तों को अंधेरे में रखा गया था। इससे पहले दिन में ईसीआई ने एक प्रमुख अखबार की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि दो चुनाव आयुक्तों ने चुनाव आयोग के कई फैसलों पर ÷आधिकारिक तौर पर आपत्ति÷ जताई थी, जो कथित तौर पर उनकी जानकारी के बिना लिए गए थे। इस मामले की सीधी जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि चुनाव आयोग के किसी भी फैसले पर किसी चुनाव आयुक्त ने कोई असहमति दर्ज नहीं कराई थी। उन्होंने कहा कि दोनों आयुक्तों ने केवल कुछ टिप्पणियां की थीं, जिनकी बाद में आयोग ने समीक्षा की थी।

महिला सुरक्षा की मांग को लेकर छात्राओं ने निकाला मार्च

दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में लेडी श्री राम कॉलेज की छात्राओं ने मार्च निकाला। छात्राओं ने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा की मांग की। लेडी श्री राम कॉलेज आज भी बंद रहा । 25 सितंबर को भी मार्च निकाला जाएगा। प्रदर्शन के दौरान एक छात्रा ने पीड़िता के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उसने कहा कि वे सिर्फ इस पीड़िता का नहीं, बल्कि देश और राजधानी में ऐसी घटनाओं का शिकार हुई सभी लड़कियों का समर्थन कर रहे हैं। यह एक सॉलिडेटरी मार्च था। उस लड़की के साथ इतनी भयानक घटना हुई है, हम पीड़िता को सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ उसी के साथ नहीं, बल्कि देश और राजधानी में जितनी भी लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, हम उन सभी के समर्थन में यहां आए हैं। आस्था कुंज पार्क में कथित सामूहिक दुष्कर्म के बाद दिल्ली पुलिस ने मॉरिस नगर और दिल्ली विश्वविद्यालय उत्तरी परिसर के पास गश्त बढ़ा दी है। इसमें पैदल, स्कूटर गश्त और पिंक पुलिस टीमें तैनात की गई हैं।

राज रानी एक्सप्रेस की चपेट में आए पांच युवक, चार की मौत; एक की हालत गंभीर



एजेंसी

श्रीकाकुलम। श्रीकाकुलम जिले में राज रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से चार युवकों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पांचों युवक रेलवे ट्रैक पर चल रहे थे और मछली पकड़ने के बाद लौट रहे थे। सभी डामरू गांव के रहने वाले और छात्र बताए गए हैं। पुलिस हादसे की पूरी परिस्थितियों की जांच कर रही है।

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में बुधवार को दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ। टेक्काली मंडल के रविवलासा के पास राज रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से चार युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव का काम शुरू किया। पुलिस के मुताबिक, पांचों युवक रेलवे ट्रैक पर चल रहे थे, तभी राज रानी एक्सप्रेस ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। ट्रेन भुवनेश्वर से गुनुपुर की ओर जा रही थी। हादसे में चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

शुरुआती पुलिस जानकारी के अनुसार, ये युवक तालाब में मछली पकड़ने के बाद रविवलासा की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान वे रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वे ट्रैक पर किस वजह से चल रहे थे और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ।

भाजपा ने स्मृति ईरानी को हरियाणा व विनोद तावड़े को यूपी का बनाया प्रभारी

एजेंसी



नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नयी महासचिव स्मृति ईरानी को हरियाणा एवं दादरा नगर हवेली, विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश, सतीश पूनिया को पंजाब एवं जम्मू कश्मीर तथा विप्लब देव को मध्य प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी ने अगस्त में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नियुक्ति के एक माह बाद राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के नये प्रभारियों एवं सह-प्रभारियों की बुधवार को घोषणा की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन द्वारा अनुमोदित इन नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने यहां एक विज्ञप्ति में यह सूची जारी की जिसके अनुसार, दिल्ली का प्रभारी विनय सहस्रबुद्धे को बनाया गया है, जबकि जामयांग त्सेरिंग नामग्याल और दर्शना बेन जरदोश को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। गुजरात का प्रभारी तरुण चुघ और सह प्रभारी अजय महावर तथा गोमती साई होंगी। हरियाणा में स्मृति ईरानी को प्रभारी तथा भोला सिंह को सह प्रभारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में स्मृति ईरानी को प्रभारी और सिद्धार्थ शंभू को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश का प्रभारी विनोद तावड़े को बनाया गया है, जबकि जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, प्रदीप वर्मा और अनंत ओझा को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र का प्रभारी बैजयंत जय पांडा और सह प्रभारी अमित मालवीय, सदानंद शेट तानावडे तथा कमलजीत सहरावत को बनाया गया है। राजस्थान में संजय भाटिया को प्रभारी तथा कविता पाटीदार और कुलजीत चहल को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है।

पार्टी ने कर्नाटक का प्रभारी हरीश द्विवेदी, केरलम का प्रभारी प्रो. एम. नागराजा, मध्य प्रदेश का प्रभारी बिप्लब कुमार देव, ओडिशा का प्रभारी डी. पुरंदेश्वरी, पंजाब एवं जम्मू-कश्मीर का प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया और पश्चिम बंगाल एवं तेलंगाना का प्रभारी सुनील बंसल को बनाया है। जम्मू-कश्मीर में सह प्रभारी रीना कश्यप होंगी। आंध्र प्रदेश में अरविंद भदौरिया को प्रभारी और वनथी श्रीनिवासन को सह प्रभारी, असम में मंगल पांडे को प्रभारी तथा फांग्नोन कोन्याक और मनोज टिग्गा को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। बिहार में हरीश द्विवेदी को प्रभारी तथा संगीता यादव और रोहन गुप्ता को सह प्रभारी बनाया गया है। पार्टी ने उत्तराखंड में राम माधव को प्रभारी तथा अरविंद मेनन और बांसुरी स्वराज को सह प्रभारी बनाया है। तेलंगाना में सुनील बंसल को प्रभारी तथा अभय पाटिल और रेखा शर्मा को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश का प्रभारी श्रीकांत शर्मा और सह प्रभारी दर्शना सिंह को बनाया गया है। इसके अलावा जय प्रकाश को अंडमान और निकोबार का, देवेश कुमार को अरुणाचल प्रदेश का, महेंद्र पांडे को चंडीगढ़ का, वर्षाबेन नरेन्द्रभाई दोशी को दादरा नागर हवेली और दमन एवं दीव का प्रभारी का प्रभारी बनाया गया है। वहीं गोवा का प्रभारी डॉ. भारती प्रवीण पवार और सह प्रभारी अनिल एंटनी को बनाया गया है।

ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो और एसआईआर रोका जाए, चुनाव आयोग पर खुलासे के बाद विपक्ष की मांग

एजेंसी



नई दिल्ली। देश में निष्पक्ष चुनाव कराने वाली संवैधानिक संस्था है, लेकिन आज इसी संस्था के भीतर कथित मतभेदों को लेकर सियासत गरमा गई है. 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक पड़ताल में दावा किया गया है कि पिछले 10 महीनों में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में लिए गए फैसलों पर कम से कम 14 बार लिखित आपत्ति दर्ज कराई. रिपोर्ट सामने आते ही विपक्ष ने श्रष्ट पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है. राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने और विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया रोकने की मांग की है. वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग की ओर से यह कहा गया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।

कपिल सिब्बल ने क्या-क्या मांग रखीं?

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इससे भी आगे जाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग की. सिब्बल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के तीन सदस्यों में बहुमत ज्ञानेश कुमार के साथ नहीं था और इसके बावजूद फैसले लिए गए. उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया रोकने, हाल में हुए कुछ चुनावों को रद्द करने और पूरे मामले की जांच की मांग भी की. सिब्बल ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को मामले का

अखिलेश यादव ने क्या कहा?

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस रिपोर्ट को गंभीर बताया. उन्होंने कहा कि अगर स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के सदस्यों को अपने तरीके से काम करने की स्वतंत्रता नहीं है या उनकी सुनवाई नहीं होती तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर स्थिति है. अखिलेश यादव ने सर्वोच्च न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की यानी उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे को चुनावी और लोकतांत्रिक बहस का हिस्सा बना रही है।

संजय राउत से लेकर कांग्रेस तक हमलावर

शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और कार्रवाई की मांग की. कांग्रेस के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने मुख्य चुनाव आयुक्त को कानूनी संरक्षण देने वाले 2023 के कानून को भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाने की मांग की। वहीं सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि अगर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताए गए तथ्य सही हैं तो इससे चुनाव आयोग के कामकाज पर गंभीर

विपक्ष को मिला बड़ा राजनीतिक मुद्दा

जैसे ही यह रिपोर्ट सामने आई तो विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी मनमर्जी से फैसले कर रहे हैं. कांग्रेस के मुताबिक, दो चुनाव आयुक्तों ने लगातार आपत्तियां दर्ज कराई और उन्हें नजरअंदाज किया गया. कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता से जोड़ते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की है।

संजय सिंह बोले- ज्ञानेश कुमार को जेल भेजना चाहिए

आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने CEC ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है. उन्होंने कहा कि दो चुनाव आयोग कह रहे है कि आपका वोट काटने का तरीका गलत है, चुनाव का तरीका अब क्या बचा, मैंने बिहार के वक्त बचा था अब बस प्रमाण पत्र देना बाकि है, बिहार के चुनाव में लूट हुई, मोदी-शाह और ज्ञानेश मिलकर चुनाव लूट रहे है, जो लोगों ने नाम आपने काटे उनके लिए जेल कौन जाएगाज ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल में डालना चाहिएज इनके रहते अब कोई चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते, जितने चुनाव हुए है वो कैंसिल हो, ये तो लूट की प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट आंखो पर पट्टी बांधकर बैठा है.

14 आपत्तियों पर सियासी हलचल

'द इंडियन एक्सप्रेस' की 23 सितंबर की पड़ताल के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार चुनाव आयोग के कुछ फैसलों और आदेशों पर औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई. रिपोर्ट के मुताबिक, एक दिन में ही चार बार आपत्ति दर्ज की गई. इन आपत्तियों में मुख्य तौर पर नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची से नाम हटाने और जोड़ने, हटाए गए मतदाताओं के नाम बहाल करने से जुड़े फैसलों, प्रपत्र-6 में बदलाव और मतदाता सूची तक पहुंच जैसे मुद्दे शामिल थे। दोनों चुनाव आयुक्तों ने कुछ कदमों को कथित तौर पर अनधिकृत और अवैध बताया. इस विवाद की एक बड़ी कड़ी प्रपत्र-6 है. यही वह प्रपत्र है जिसका इस्तेमाल नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए किया जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल जुलाई में इसमें ऐसा सवाल जोड़ा गया, जिसमें नए मतदाता से यह पूछा जा रहा था कि उसका नाम या उसके माता-पिता अथवा दादा-दादी का नाम पिछली विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (स्क्रूच) की मतदाता सूची में था या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक, मई में ही चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने इस बदलाव पर आपत्ति दर्ज की थी. उनका कहना था कि प्रपत्र-6 वैधानिक प्रपत्र है और इसमें बदलाव के लिए संबंधित नियमों में संशोधन जरूरी है. सुखबीर सिंह संधू ने भी बाद में इस बदलाव को कथित तौर पर अनधिकृत और अवैध बताते हुए इसे तत्काल हटाने की बात कही. इसके बावजूद रिपोर्ट के मुताबिक, यह सवाल कुछ समय तक प्रपत्र में मौजूद रहा।

वोटर लिस्ट को लेकर भी सवाल?

मतदाता सूची तैयार करने और उसमें नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल के मुताबिक, दोनों चुनाव आयुक्तों ने मतदाता सूची से जुड़े सूचना-तंत्र के धीरे-धीरे केंद्रीकृत होने पर चिंता जताई. रिपोर्ट के अनुसार विवेक जोशी ने मई में मतदाता सूची के आंकड़ों के केंद्रीकरण पर सवाल उठाया। उन्होंने इस बात की जांच की जरूरत बताई कि संबंधित वैधानिक अधिकारियों के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के पास मतदाता आंकड़ों में बदलाव करने की पहुंच तो नहीं है. सुखबीर सिंह संधू ने भी बाद में राज्य स्तर के अधिकारियों की सूचना-तंत्र तक पहुंच सीमित होने की शिकायत दर्ज की।

चुनाव आयोग ने क्या कहा?

रिपोर्ट सामने आने के बाद चुनाव आयोग की ओर से यह कहा गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं.

बागी टीएमसी सांसदों की अयोग्यता पर फैसला कब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि लोकसभा अध्यक्ष से तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी की ओर से 20 बागी टीएमसी सांसदों को संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने की उम्मीद है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ बनर्जी की ओर से दायर उस रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष से इन याचिकाओं पर समयबद्ध फैसला लेने की मांग की गई है। अभिषेक बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बंदोपाध्याय पेश हुए। उन्होंने कहा कि अगस्त में लोकसभा अध्यक्ष ने बागी सांसदों को नोटिस जारी किए थे, लेकिन उन्होंने शुरुआती 14 दिन की अवधि में अपने जवाब दाखिल नहीं किए। उन्होंने बताया कि इसके बाद अध्यक्ष ने जवाब दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 22 सितंबर कर दी थी। इसके बावजूद सांसदों ने फिर समय बढ़ाने की मांग की है।

संपादकीय

ज़िंदगी के रेतिले टीलों में जीवन का एकाकीपन

संपादक की कलम से...

कभी-कभी अपनों के बुरे बर्ताव से होने वाला दुख शरीर के अंगों को हमेशा के लिए नुकसान पहुँचा सकता है। ज़िंदगी सभी के लिए एक मुश्किल सफ़र है। इसीलिए, राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई; जब (बुद्ध बनने से पहले) उन्होंने अपना महल छोड़ा, तो उन्हें 'चार दृश्य' यानी इंसानी ज़िंदगी की चार सच्चाइयाँ दिखाई दीं, जिनसे उनके पिता ने उन्हें दूर रखा था। वे चार दृश्य थे: एक बूढ़ा आदमी की झुर्रियां, सफ़ेद बालों और झुकी हुई पीठ वाला कमज़ोर इंसान, जिसने उन्हें दिखाया कि बुढ़ापा हर किसी को आता है। एक बिमार आदमी; बिमारी से जूझता हुआ इंसान, जिसने उन्हें दिखाया कि दर्द व बिमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। एक मृत आदमी–अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा शव, जिसने उन्हें दिखाया कि मौत सभी के लिए तय है। एक घूमता हुआ साधु, शांत और सुकून भरा साधक जिसने दुःखों की सच्चाई जानने के लिए दुनियादारी छोड़ दी थी, जिससे राजकुमार को उम्मीद मिली कि इसका कोई जवाब मौजूद है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को अंदर तक हिला दिया और उन्हें एहसास कराया कि दौलत और ऐशो-आराम किसी को भी दुःख, बुढ़ापे या मौत से नहीं बचा सकते। इस गहरी समझ ने उन्हें अपनी शाही ज़िंदगी छोड़कर आध्यात्मिक सच्चाई की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। हालाँकि 'मैं हिंदू हूँ', फिर भी मेरी ज़िंदगी पर बुद्ध के जीवन का बहुत असर पड़ा। मेरा जन्म अविभाजित जम्मू-कश्मीर के सराफ़ और महाजन परिवार में हुआ था। 1947 में भारत के बँटवारे की भयानक त्रासदी का उन लोगों पर गहरा असर पड़ा जो कश्मीर की तरफ़ से आए थे। मेरी माँ श्रीमती लज्जा देवी और पिता श्री जसवंत राय जी ने मीरपुर [जो अब पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर में है] में खरबों की कीमत का सोना-चाँदी छोड़ दिया था। वे बहादुर और हिम्मत वाले थे, जिन्होंने जम्मू और फिर दिल्ली में अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू की। मेरे पिता अरबपति थे, लेकिन सादा जीवन जीते थे। उन्होंने युद्ध में बेघर हुए शरणार्थियों का एक मुख्य कार्य समूह बनाया। प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन आवास मंत्री मेहर चंद खन्ना के साथ कई बैठकों के बाद, दिल्ली के पटेल नगर, राजेंद्र नगर, लाजपत नगर और अन्य इलाकों में घर आवंटित किए गए। ८

भारत में डेंगू वैक्सीन की दस्तक: बीमारी के खिलाफ नई उम्मीद

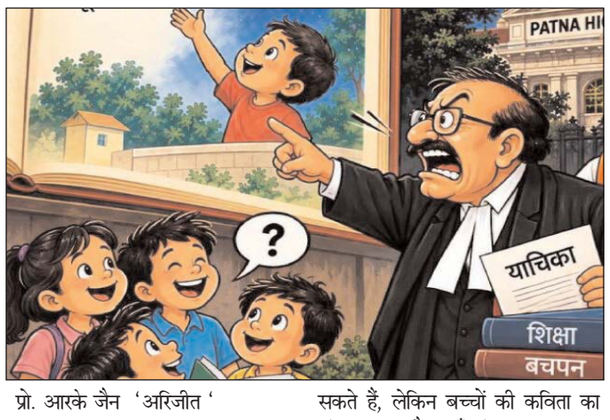
सौरभ वार्ष्णेय



भारत में डेंगू लंबे समय से एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है। हर वर्ष देश के अलग-अलग हिस्सों में डेंगू के मामले सामने आते हैं और कई लोगों की जान भी चली जाती है। बदलते मौसम, शहरीकरण, जलभराव और मच्छरों के प्रजनन के अनुकूल परिस्थितियों के कारण डेंगू का दायरा लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं इसका आतंक बड़े बड़े शहरों में अधिक है, ऐसे समय में डेंगू के खिलाफ वैक्सीन का भारत में उपलब्ध होने की खबर निश्चित रूप से उम्मीद जगाती है। यदि सब कुछ तय प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ता है तो देश में पहली डेंगू वैक्सीन के रूप में टेकेडा फार्मास्यूटिकल्स की 'क्यूडेंगा आने वाले वर्षों में लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है। जापानी कंपनी टेकेडा फार्मास्यूटिकल्स और हैदराबाद स्थित डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज के बीच हुआ समझौता इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समझौते के तहत डॉ. रेड्डीज भारत के निजी बाजार में टेकेडा की क्यूडेंगा वैक्सीन के प्रमोशन और वितरण की जिम्मेदारी निभाएगी। कंपनियों के अनुसार, वैक्सीन को 2027 की पहली छमाही में भारत में लॉन्च किए जाने की संभावना है। हालांकि, इसके लिए आवश्यक स्थानीय नियामकीय और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को पूरा करना अभी बाकी है। डेंगू के खिलाफ वैक्सीन का भारत में प्रवेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक इस बीमारी से बचाव का मुख्य आधार मच्छरों की रोकथाम, साफ-सफाई और संक्रमित व्यक्ति की समय पर चिकित्सकीय देखभाल ही रहा है। डेंगू के लिए कोई ऐसी व्यापक रूप से उपलब्ध दवा नहीं है जो संक्रमण को सीधे खत्म कर सके। ऐसे में रोकथाम के लिए वैक्सीन की उपलब्धता सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में एक नया विकल्प जोड़ सकती है। हालांकि, किसी भी नई वैक्सीन को लेकर उत्साह के साथ-साथ कुछ बुनियादी सवालों पर गंभीरता से विचार करना भी जरूरी है। सबसे पहला सवाल इसकी कीमत का है। फिलहाल क्यूडेंगा की भारत में कीमत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। टेकेडा के इंटरकॉन्टिनेंटल मार्केट्स के प्रमुख महेंद्र नायक के अनुसार, भारत में मार्केटिंग ऑथराइजेशन की मंजूरी मिलने के बाद अभी स्थानीय प्रक्रियाओं को पूरा करना प्राथमिकता है। इन प्रक्रियाओं के पूरा होने से पहले वैक्सीन की कीमत का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी। कीमत का सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डेंगू केवल महानगरों या संपन्न वर्ग की समस्या नहीं है। इसका प्रभाव छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों तक दिखाई देता है। यदि वैक्सीन निजी बाजार में आती है और इसकी कीमत आम परिवारों की पहुंच से बाहर रहती है, तो इसका लाभ सीमित आबादी तक ही सिमट सकता है। इसलिए वैक्सीन की उपलब्धता जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण उसकी सामर्थ्य भी है। यहां सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कंपनियों ने संकेत दिया है कि क्यूडेंगा को भारत के सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करना एक दीर्घकालिक लक्ष्य है। निजी बाजार में वैक्सीन की उपलब्धता शुरुआती चरण हो सकती है, लेकिन व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव तभी संभव होगा जब जरूरत और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर इसे सरकारी टीकाकरण व्यवस्था में शामिल करने पर विचार किया जाए। किसी वैक्सीन को सार्वजनिक कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय केवल उसकी उपलब्धता के आधार पर नहीं होता। इसके लिए बीमारी का बोझ, वैक्सीन की प्रभावशीलता, सुरक्षा, अलग-अलग आयु समूहों में उसका प्रदर्शन, लागत-प्रभावशीलता और स्वास्थ्य व्यवस्था पर संभावित प्रभाव जैसे अनेक पहलुओं का मूल्यांकन आवश्यक होता है। भारत जैसे विशाल और विविध आबादी वाले देश में यह प्रक्रिया और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यूडेंगा की भारत में उपलब्धता का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जागरूकता से जुड़ा है। डेंगू को लेकर समाज में अभी भी कई भ्रांतियां मौजूद हैं। कई बार लोग बुखार को सामान्य वायरल संक्रमण समझकर इलाज में देरी करते हैं। वहीं कुछ लोग डेंगू की रोकथाम को केवल मच्छर भगाने तक सीमित मानते हैं। वास्तव में डेंगू नियंत्रण के लिए व्यक्तिगत सावधानी, मच्छर नियंत्रण, स्वच्छता, समय पर जांच और चिकित्सकीय सलाह–सभी की जरूरत होती है। वैक्सीन के आने के साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा कि लोग इसे डेंगू से बचाव की एक अतिरिक्त रणनीति के रूप में समझें, न कि अन्य सावधानियों के विकल्प के रूप में। डॉ. रेड्डीज और टेकेडा के बीच सहयोग का उद्देश्य केवल वैक्सीन का वितरण नहीं है। कंपनियों के अनुसार, इसके तहत डेंगू के बारे में जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ जुड़ाव को भी महत्व दिया जाएगा। यह पहल इसलिए उपयोगी हो सकती है क्योंकि वैक्सीन से जुड़े निर्णय में डॉक्टरों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। योग्य लोगों को वैक्सीन की जरूरत, संभावित लाभ और सीमाओं के बारे में सही जानकारी चिकित्सकीय परामर्श के माध्यम से ही मिलनी चाहिए। भारत में पहली डेंगू वैक्सीन के आने की संभावित खबर को इसलिए एक शुरुआत के रूप में देखा जाना चाहिए, अंतिम समाधान के रूप में नहीं। डेंगू की चुनौती केवल वैक्सीन से खत्म नहीं होगी। मच्छरों के प्रजनन स्थलों को समाप्त करना, जलभराव रोकना, साफ-सफाई बनाए रखना, समय पर बीमारी की पहचान करना और अस्पतालों में उचित उपचार की व्यवस्था करना भी उतना ही आवश्यक रहेगा। सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि वैक्सीन डेंगू से निपटने की मौजूदा रणनीति को मजबूत कर सकती है। लेकिन इसके साथ यह सावधानी भी जरूरी है कि वैज्ञानिक प्रमाण, नियामकीय मानक और सार्वजनिक स्वास्थ्य की जरूरतें व्यावसायिक हितों से ऊपर रहें।

वहीं कुछ लोग डेंगू की रोकथाम को केवल मच्छर भगाने तक सीमित मानते हैं। वास्तव में डेंगू नियंत्रण के लिए व्यक्तिगत सावधानी, मच्छर नियंत्रण, स्वच्छता, समय पर जांच और चिकित्सकीय सलाह–सभी की जरूरत होती है। वैक्सीन के आने के साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा कि लोग इसे डेंगू से बचाव की एक अतिरिक्त रणनीति के रूप में समझें, न कि अन्य सावधानियों के विकल्प के रूप में। डॉ. रेड्डीज और टेकेडा के बीच सहयोग का उद्देश्य केवल वैक्सीन का वितरण नहीं है। कंपनियों के अनुसार, इसके तहत डेंगू के बारे में जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ जुड़ाव को भी महत्व दिया जाएगा। यह पहल इसलिए उपयोगी हो सकती है क्योंकि वैक्सीन से जुड़े निर्णय में डॉक्टरों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। योग्य लोगों को वैक्सीन की जरूरत, संभावित लाभ और सीमाओं के बारे में सही जानकारी चिकित्सकीय परामर्श के माध्यम से ही मिलनी चाहिए। भारत में पहली डेंगू वैक्सीन के आने की संभावित खबर को इसलिए एक शुरुआत के रूप में देखा जाना चाहिए, अंतिम समाधान के रूप में नहीं। डेंगू की चुनौती केवल वैक्सीन से खत्म नहीं होगी। मच्छरों के प्रजनन स्थलों को समाप्त करना, जलभराव रोकना, साफ-सफाई बनाए रखना, समय पर बीमारी की पहचान करना और अस्पतालों में उचित उपचार की व्यवस्था करना भी उतना ही आवश्यक रहेगा। सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि वैक्सीन डेंगू से निपटने की मौजूदा रणनीति को मजबूत कर सकती है।

लोरी मासूम थी, शायद हमारी नजर बड़ी हो गई



प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

भाषा केवल शब्दों की गठरी नहीं होती; वह समय की स्मृति, समाज की संवेदना और पीढ़ियों की साझा सांस होती है। 'चंदा मामा दूर के, पूए पकाए बूर के' इसी जीवित परंपरा का गीत है, जिसे न जाने कितनी नानी-दादियों ने बच्चों को थपकी देते हुए गाया और कितनी पीढ़ियों ने चाँद को अपना मामा मानकर आँखें मूंद लीं। अब उसी लोरी के 'बूर' शब्द पर आपत्ति उठ रही है। प्रश्न यह नहीं कि किसी शब्द का आज कोई दूसरा अर्थ निकाला जा सकता है या नहीं; प्रश्न यह है कि क्या आज की दृष्टि से कल की मासूमियत को कठघरे में खड़ा किया जाना चाहिए? यदि किसी शब्द की वर्तमान व्याख्या बदल गई है, तो क्या उसके साथ सदियों की स्मृति भी बदल दी जाए? भाषा का सबसे बड़ा सौंदर्य यही है कि एक ही शब्द में कई अर्थों की संभावनाएं सँजोए रहती हैं। संदर्भ बदलते ही अर्थ का रंग बदल जाता है। 'कली', 'फूल', 'नदी', 'बूर' जैसे शब्द अलग संदर्भों में अलग अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की कविता का संसार अलग है। वहाँ चंदा मामा सचमुच मामा हैं, पूए सचमुच पूए हैं और 'बूर' भी उसी घरेलू, खाद्य और लोक-प्रचलित संदर्भ में समझा जाता रहा है। किसी शब्द को उसके मूल संदर्भ से निकालकर आधुनिक द्विअर्थी चश्मे से देखना भाषा की गलती नहीं, हमारी दृष्टि का परिवर्तन है। लोरी में अश्लीलता खोजने से पहले यह देखना होगा कि वह वहाँ थी भी या हमने बाद में उसमें डाल दी। विडंबना यह है कि जिस समय समाज की मुख्यधारा में जानबूझकर उत्तेजक भाषा धड़ल्ले से परोसी जा रही है, हमारी चिंता एक पुरानी लोरी के शब्द पर ठहर गई है। फिल्मों के संवाद, गीतों के बोल, इंटरनेट के मीम्स और स्टैंड-अप कॉमेडी में ऐसे शब्द और संकेत लगातार सामने आते हैं, जिनका उद्देश्य चौंकाना, उत्तेजित करना या हँसी के नाम पर अभद्रता को सामान्य बनाना होता है। वहां उनका आशय भी स्पष्ट होता है। ऐसे में पारंपरिक बालगीत के एक शब्द को उसी तराजू पर तौलना नैतिकता की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़ा करता है। चिंता वहां होनी चाहिए, जहां अश्लीलता इरादतन रची जा रही है, न कि वहां जहां पीढ़ियों से मासूमियत सांस लेती आई है। द्विअर्थी शब्द किसी एक भाषा की बीमारी नहीं हैं। लगभग हर भाषा में ऐसे शब्द हैं, जिनके अर्थ संदर्भ, समय, क्षेत्र और प्रयोग के साथ बदलते रहे हैं। समस्या तब होती है, जब हम किसी पुराने शब्द को उसके सांस्कृतिक परिवेश से काटकर केवल आज की संवेदना के आईने में देखने लगते हैं। बच्चे जब 'चंदा मामा' सुनते हैं तो उनके मन में चाँद, मामा और पूए की प्यारी तस्वीर बनती है; वहाँ किसी वयस्क संकेत की जगह नहीं होती। यदि कोई वयस्क उस मासूम संसार में दूसरा अर्थ खोजता है तो दोष शब्द का नहीं हो सकता। बच्चों की दुनिया को वयस्क मानसिकता से पढ़कर कविता बदल देना भाषा सुधारना नहीं, अपनी दृष्टि की सीमा रचना पर थोपना है। लेकिन यदि आज एक शब्द असुविधाजनक लग रहा है तो कल कितने शब्दों की बारी आएगी? क्या लोकगीतों के मुहावरे, कहावतों और पुराने कवियों के शब्द भी आज की कसौटी पर छांटे जाएंगे? कबीर, तुलसी और मीरा की रचनाओं में भी ऐसे शब्द, बिंब और संदर्भ हैं जिन्हें आज का पाठक अलग तरह से देख सकता है। क्या हर पीढ़ी अपनी सुविधा के अनुसार पुरानी रचनाओं को संपादित करती चले? संस्कृति नदी की तरह बहती है; उसमें समय का पानी मिलना स्वाभाविक है, लेकिन उसे बचाने के नाम पर उसका उद्गम मिटा देना समझदारी नहीं। विरासत का अर्थ हर पुरानी चीज को पूजनीय मानना नहीं, बल्कि उसे उसके समय और संदर्भ के साथ समझना है।

छात्रों के कार्यक्रम में नकारात्मक राजनीति क्यों?

सुरेश हिंदुस्तानी

लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति संवाद है। सरकार और विपक्ष के बीच वैचारिक विरोध होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन जब राजनीतिक संवाद का केंद्र नीतियों और जनसमस्याओं से हटकर व्यक्तियों पर टिप्पणियों, आरोपों, कटाक्षों और उपहास तक सीमित होने लगे तो लोकतांत्रिक विमर्श की गंभीरता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। वर्तमान में भारत की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजनीतिक दल रचनात्मक विरोध की जगह अनुचित आरोप प्रत्यारोप की परिधि में लगातार सक्रिय हैं। इस प्रकार की राजनीति देश के लोकतंत्र के उत्थान का मार्ग बिलकुल भी तैयार नहीं कर सकती। अभी कुछ पूर्व इंदौर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम से जुड़ा मिमिक्री विवाद इसका ताजा उदाहरण है। कार्यक्रम का मूल विषय विद्यार्थियों की समस्याओं, शिक्षा, परीक्षाओं, रोजगार और छात्रावास जैसी चिंताओं से जुड़ा था। लेकिन ऐसा लगा कि कार्यक्रम अपने मूल उद्देश्य से भटक कर आरोपों और व्यक्तिगत खिल्ली उडाने पर ही केंद्रित होकर रह गया। आज चिंता इस बात की है कि छात्रों के सामने समस्या नहीं समाधान की चर्चा होना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों के सामने इस अंदाज में अपनी बात रखने का प्रयास किया कि छात्र सरकार के विरोध में खड़े हो जाएं। जिन बातों का उल्लेख छात्रों के समक्ष होना चाहिए, वे मुद्दे भी कार्यक्रम में पूरी तरह गायब दिखाई दिए। ऐसे में सवाल उठता है कि हमारे राजनीतिक दल छात्रों को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हालांकि कार्यक्रम में कुछ मुद्दों पर सरकार पर सवाल भी उठाए। लेकिन ऐसे सवाल छात्रों के बीच नहीं आना चाहिए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते राजनीतिक बहस का प्रमुख विषय बन गया। विपक्ष की ओर से इसे राजनीतिक व्यंग्य और अभिव्यक्ति के अधिकार के संदर्भ में देखा गया। क्या अभिव्यक्ति इस प्रकार की होना चाहिए, कदापि नहीं।

यहां प्रश्न केवल मिमिक्री का नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या राजनीतिक कार्यक्रमों में गंभीर मुद्दों को केंद्र में रखने के बजाय व्यक्तिगत कटाक्ष और उपहास को अधिक स्थान मिलना चाहिए? राजनीति में व्यंग्य कोई नई बात नहीं है। लोकतंत्र में व्यंग्य सत्ता से सवाल पूछने का माध्यम भी रहा है। नेता, सरकारें और नीतियां आलोचना के विषय बनती रही हैं। लेकिन व्यंग्य और व्यक्तिगत अवमानना के बीच एक महीन रेखा होती है। राजनीतिक विरोध कितना तीखा हो, यह राजनीतिक परिस्थितियां तय कर सकती हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भाषा और व्यवहार की मर्यादा का प्रश्न हमेशा बना रहता है। इंदौर की घटना में भी यही बहस सामने आई। इस पूरे प्रसंग से एक बड़ा सवाल जरूर निकलता है कि क्या विद्यार्थियों के मंच पर विद्यार्थियों के मूल प्रश्न पीछे छूट जाने चाहिए? यदि किसी छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही, यदि परीक्षा व्यवस्था को लेकर उसके मन में चिंता है, यदि रोजगार उसके भविष्य का सबसे बड़ा प्रश्न है या किसी छात्रा के सामने सुरक्षित और किफायती आवास की समस्या है, तो राजनीति का दायित्व है कि वह इन प्रश्नों को मजबूती से उठाए। इन सवालों के उत्तर भी उसी गंभीरता से मांगे जाने चाहिए। विपक्ष यदि सरकार की शिक्षा नीति से असहमत है तो उसे आंकड़ों के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए। सरकार यदि विपक्ष के आरोपों को गलत मानती है तो उसे आंकड़ों और तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए। यही स्वस्थ लोकतांत्रिक बहस का रास्ता है। दुर्भाग्य यह है कि आज आरोप लगाना आसान हो गया है और आरोप का जवाब भी एक नए आरोप से देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। एक नेता किसी नीति पर सवाल उठाता है तो जवाब में नीति की चर्चा करने के बजाय उसके पुराने बयान खोजे जाते हैं। किसी सरकार के निर्णय पर सवाल उठता है तो विपक्ष के पुराने कार्यकाल की कमियां गिनाई जाती हैं। किसी नेता की आलोचना होती है तो उसके जवाब में दूसरे नेता की आलोचना सामने आ जाती है। इस प्रकार राजनीतिक संवाद एक ऐसी प्रतिस्पर्धा में बदल जाता है जिसमें यह साबित करने की कोशिश होती है कि सामने वाला अधिक गलत है। लेकिन जनता का सवाल इससे अलग है कि आप क्या करेंगे? राजनीतिक दलों की ठोस योजनाएं क्या हैं। इन सवालों का उत्तर किसी आरोप से नहीं दिया जा सकता। राजनीति में व्यक्तिगत आक्षेप इसलिए भी चिंता का विषय हैं क्योंकि वे धीरे-धीरे राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन जाते हैं। नेता जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। समर्थक उसी भाषा को दोहराते हैं और फिर राजनीतिक मतभेद सामाजिक कटुता में बदलने लगते हैं। लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध का अर्थ वैमनस्य नहीं है। आज विपक्ष की ओर से सरकार के प्रति पूरी तरह कटुता का व्यवहार किया जा रहा है। इंदौर के कार्यक्रम में भी कटुता का खेल खेला गया।

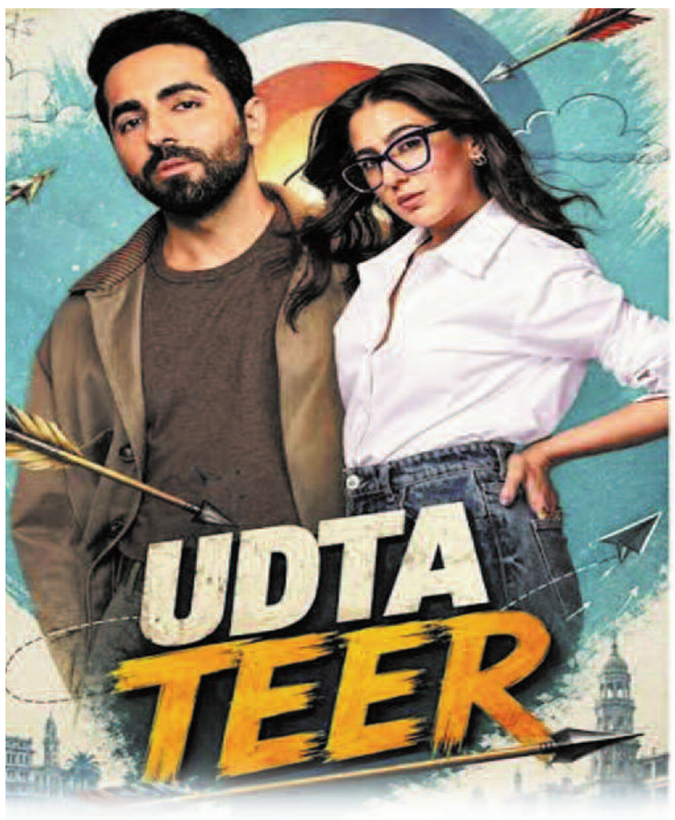
यदि रोजगार उसके भविष्य का सबसे बड़ा प्रश्न है या किसी छात्रा के सामने सुरक्षित और किफायती आवास की समस्या है, तो राजनीति का दायित्व है कि वह इन प्रश्नों को मजबूती से उठाए। इन सवालों के उत्तर भी उसी गंभीरता से मांगे जाने चाहिए। विपक्ष यदि सरकार की शिक्षा नीति से असहमत है तो उसे आंकड़ों के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए। सरकार यदि विपक्ष के आरोपों को गलत मानती है तो उसे आंकड़ों और तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए। यही स्वस्थ लोकतांत्रिक बहस का रास्ता है। दुर्भाग्य यह है कि आज आरोप लगाना आसान हो गया है और आरोप का जवाब भी एक नए आरोप से देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। एक नेता किसी नीति पर सवाल उठाता है तो जवाब में नीति की चर्चा करने के बजाय उसके पुराने बयान खोजे जाते हैं। किसी सरकार के निर्णय पर सवाल उठता है तो विपक्ष के पुराने कार्यकाल की कमियां गिनाई जाती हैं। किसी नेता की आलोचना होती है तो उसके जवाब में दूसरे नेता की आलोचना सामने आ जाती है। इस प्रकार राजनीतिक संवाद एक ऐसी प्रतिस्पर्धा में बदल जाता है जिसमें यह साबित करने की कोशिश होती है कि सामने वाला अधिक गलत है। लेकिन जनता का सवाल इससे अलग है कि आप क्या करेंगे? राजनीतिक दलों की ठोस योजनाएं क्या हैं। इन सवालों का उत्तर किसी आरोप से नहीं दिया जा सकता। राजनीति में व्यक्तिगत आक्षेप इसलिए भी चिंता का विषय हैं क्योंकि वे धीरे-धीरे राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन जाते हैं। नेता जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। समर्थक उसी भाषा को दोहराते हैं और फिर राजनीतिक मतभेद सामाजिक कटुता में बदलने लगते हैं। लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध का अर्थ वैमनस्य नहीं है। आज विपक्ष की ओर से सरकार के प्रति पूरी तरह कटुता का व्यवहार किया जा रहा है। इंदौर के कार्यक्रम में भी कटुता का खेल खेला गया।

एआई वीडियो-पोस्टरों से गरमायी यूपी की सियासत

संजय सक्सेना



2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत सोशल मीडिया पर एक नई शक्ल में उतर आई है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच अब पारंपरिक भाषण-बाज़ी से आगे बढ़कर एआई-निर्मित वीडियो और पोस्टरों की जंग छिड़ गई है, जिसे कई हलकों में एआई वॉर कहा जा रहा है। हालिया मामले की बात की जाए तो वह ताज़ा पोस्टर है, जिसमें अखिलेश को आजम-अतीक और मुख्तार के साथ दिखाया गया है। पोस्टर के मुख्य नारे हैं- 'आजम, अतीक और मुख्तार, यही चलाते थे सरकार।' दूसरा नारा है- 'अखिलेश के माफिया, माफिया के अखिलेश।' कुछ पोस्टरों में वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया के नारे के साथ अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े कई नाम दिखाए गए हैं। जैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान, याकूब कुरैशी, अनिल दुजाना और अवध क्षेत्र के पोस्टर में गुलशन यादव, मित्रसेन यादव और रिजवान जहीर जैसे नाम भी शामिल हैं। इसकी शुरुआत तब हुई, जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा एक एआई वीडियो जारी किया। पार्टी के अनुसार, यह वीडियो एक जवाबी कार्रवाई थी। अखिलेश यादव का कहना था कि यह वीडियो समाजवादी पार्टी का बनाया हुआ नहीं था, बल्कि किसी व्यक्ति ने उन्हें भेजा था, और यह भाजपा समर्थक हैंडलों से पहले शेयर किए गए एक वीडियो के जवाब में सामने आया। भाजपा की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रिया आई। पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत शारदा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का ऐसा वीडियो बनाना बेहद आपत्तिजनक है और इसे सपा की राजनीति के स्तर को उजागर करने वाला बताया। भाजपा नेताओं ने अखिलेश यादव से सार्वजनिक माफी मांगने और वीडियो को तुरंत हटाने की मांग रखी। वहीं, भाजपा महासचिव सुब्रत पाठक ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि संत भी हैं, और इस एआई वीडियो से सपा की सोच उजागर हुई है। इसके जवाब में सपा पीछे नहीं हटी। भाजपा की प्रतिक्रिया के बाद समाजवादी पार्टी ने एक और वीडियो पोस्ट किया, जिसमें योगी आदित्यनाथ को एआई के जरिए दिखाते हुए लिखा गया कि उत्तर प्रदेश धुएं से घुट रहा है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि पार्टी इस मोर्चे पर पीछे नहीं रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को बदनाम करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है और कहा कि अगर सरकार एआई के जरिए समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश करेगी तो पार्टी भी पीछे नहीं रहेगी। दूसरी ओर, भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी, भाजपा की छवि खराब करने के लिए रोज नया नैरेटिव तैयार करती है। परिणाम यह हुआ कि यह जंग जल्द ही डिजिटल दायरे से निकलकर सड़क पर पोस्टरों तक पहुंच गई। वाराणसी में भाजपा नेता सुधीर सिंह ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए एक पोस्टर जारी किया, जिसमें हार्पिक की बोतल पर उनकी तस्वीर लगाकर उन्हें हार्पिक का ब्रांड एंबेसडर बताया गया। दोनों दलों के कार्यकर्ता अब इस तरह की रचनात्मक (और आपत्तिजनक भी मानी जा रही) सामग्री बनाकर इस जंग को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। इस पूरे विवाद के बीच अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को लेकर एक और व्यंग्यात्मक टिप्पणी की, जिसके बाद भाजपा ने और तीखी प्रतिक्रिया दी। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। इस पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि अगर भाजपा एआई के जरिए उनके खिलाफ गाने और वीडियो बनाएगी तो समाजवादी पार्टी भी गानों से जवाब देगी। सोशल मीडिया पर जंग के साथ-साथ आरक्षण का मुद्दा भी इस चुनावी बहस के केंद्र में है। जब राज्य में आरक्षण सुधार को लेकर चर्चा शुरू हुई, तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की आरक्षण विरोधी छात्रों से मुलाकात के बाद यह मुद्दा सियासी बहस के केंद्र में आ गया। इस पर अखिलेश यादव ने भाजपा को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सुधार या समीक्षा जैसे शब्दों की आड़ में आरक्षण खत्म करने की किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं किया जा सकता, और आरक्षण को पीडीए समाज का अधिकार बताया, जिसे किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं किया जा सकता। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति की कोशिश पीडीए समाज के खिलाफ एक गहरी साजिश है। हाल ही में एक कार्यकारिणी बैठक में उन्होंने कहा कि युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी है, सरकारी नौकरियां नहीं हैं और आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया है। डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाओं का मुद्दा भी हाल में जोर पकड़ चुका है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि भाजपा शासन में 72 जिलों में 151 आंबेडकर प्रतिमाएं तोड़ी गईं और हर साल औसतन 15 से अधिक प्रतिमाएं तोड़ी गईं, जिनमें बलिया में सबसे अधिक मामले सामने आए। उन्होंने इसे जानबूझकर किया गया कृत्य बताते हुए कहा कि भाजपा संविधान बदलना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई, इसीलिए इस तरह की घटनाएं हुईं। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि दस साल के भाजपा शासन में सबसे ज्यादा आंबेडकर प्रतिमाएं तोड़ी गईं और अब वही जिम्मेदार लोग चुनाव से पहले बजट में मदद देकर गलत संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही दलितों, पिछड़ों और पीडीए वर्ग के साथ भेदभाव जारी रहने का आरोप भी दोहराया गया। दूसरी ओर, भाजपा और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति सपा को हिंदू आस्था और सामाजिक सौहार्द के विरोधी के रूप में पेश करने पर केंद्रित रही है। मुख्यमंत्री ने कई सार्वजनिक सभाओं में सपा पर सीधा हमला बोला है। रुदौली में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की आस्था भगवान राम के प्रति नहीं, बल्कि बाबर के प्रति है, क्योंकि उन्होंने अब तक राम मंदिर के दर्शन नहीं किए और अपने विधायकों को भी अयोध्या जाने से रोका। एक अन्य मौके पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी लोग राम से दूरी बनाते हैं और बाबर को आदर्श मानते हैं। योगी आदित्यनाथ ने सपा के इतिहास पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस समाजवादी आंदोलन को डॉ. राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, जनेश्वर मिश्र और मोहन सिंह जैसे चिंतकों ने ऊंचाई दी थी, आज सपा ने उसी आंदोलन को गुंडों, पेशेवर माफियाओं और अपराधियों का अड्डा बना दिया है। सपा ने इन आरोपों का जवाब भी उतनी ही तीखी भाषा में दिया है। विधान परिषद में अखिलेश यादव ने कहा कि 2017 से पहले मुख्यमंत्री के खिलाफ कई मामले दर्ज थे और समाजवादी पार्टी ने उन्हें राजनीतिक संरक्षण दिया था, और आरोप लगाया कि दंगा, आगजनी व नफरत फैलाना मुख्यमंत्री की राजनीतिक शैली का हिस्सा रहा है। शंकराचार्य से जुड़े एक विवाद पर भी अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोलते हुए सवाल उठाया कि उन्हें यह प्रमाणपत्र कहां से मिला।कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर 2027 के चुनाव से पहले यह टकराव कई मोर्चों पर एक साथ चल रहा है।एआई वीडियो और पोस्टरों की तकनीकी जंग से लेकर आरक्षण, सामाजिक न्याय, आंबेडकर प्रतिम



फिल्म 'उड़ता तीर' में डबल रोल प्ले कर सकते हैं आयुष्मान खुराना

बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की अगली फिल्म को लेकर मेकर्स ने अब तक कहानी से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं रखी है। हालांकि, फिल्म से जुड़े सूत्रों से बातचीत में कहानी और किरदारों को लेकर कुछ अहम जानकारी सामने आई है। फिल्म की पृष्ठभूमि भारत और पाकिस्तान से जुड़ी जरूर है।

भारत-पाकिस्तान की पृष्ठभूमि में काल्पनिक कहानी

फिल्म में भारत और पाकिस्तान की पृष्ठभूमि कहानी का अहम हिस्सा है। यह पूरी तरह काल्पनिक कहानी है, जिसे भारत-पाकिस्तान के संदर्भ में विकसित किया गया है। यही वजह है कि इसे हाल के दौर की उन फिल्मों से अलग माना जा रहा है, जिनकी कहानियां वास्तविक घटनाओं या सैन्य अभियानों से प्रेरित रही हैं।

फिल्म में डबल रोल प्ले कर सकते हैं आयुष्मान खुराना

फिल्म में आयुष्मान महत्वपूर्ण भूमिका में हैं और कहानी की मुख्य घटनाएं उनके किरदार के आसपास आगे बढ़ती हैं। इसकी वजह कहानी में मौजूद ट्विस्ट बताए जा रहे हैं। इसी वजह से आयुष्मान के डबल रोल में होने की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि, यह अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं है।

लाउड नहीं, सिचुएशनल कॉमेडी पर फोकस करेगी यह फिल्म

फिल्म का टोन इसे खास बनाता है। भारत-पाकिस्तान का बैकड्रॉप और डिफेंस से जुड़ी कहानी देखकर इसे गंभीर वॉर फिल्म या सीधी कॉमेडी समझना आसान हो सकता है। फिल्म में ड्रामा और कॉमेडी साथ-साथ चलती है। इसका हास्य लगातार पंचलाइन या वन-लाइनर्स पर बेस्ड नहीं है।

'धुरंधर' जैसी फिल्मों से अलग है कहानी

इसमें डिफेंस से जुड़ी दुनिया होने के बावजूद ड्रामा और कॉमेडी को भी बराबर जगह दी गई है। इसलिए इसे 'धुरंधर' जैसे युद्ध बेस्ड प्रोजेक्ट के साथ रखना सही नहीं है।

मुंबई से दिल्ली-एनसीआर तक हुई इस फिल्म की शूटिंग

फिल्म की शूटिंग मुंबई और दिल्ली में हुई है। दिल्ली-एनसीआर में भी इसके कई हिस्से शूट किए गए। खास तौर पर गुरुग्राम के एक कॉलेज की लोकेशन का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा वहां आर्मी बेस जैसा सेटअप भी तैयार किया गया था। फिल्म की दुनिया में सामान्य शहरी लोकेशन के साथ डिफेंस से जुड़े हिस्सों को भी जगह दी गई है।

सारा का किरदार डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़ा



सारा फिल्म में एक कामकाजी महिला का किरदार निभा रही हैं। उनका संबंध डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़ा बताया जा रहा है। यानी उनका किरदार सिर्फ घर या किसी पुरुष किरदार के आसपास सीमित नहीं है, बल्कि फिल्म की पेशेवर दुनिया का हिस्सा है। उनके किरदार की पूरी भूमिका अभी सामने नहीं आई है।



रिजेक्शन और रिप्लेसमेंट के बाद तारा सुतारिया ने बनाई पहचान



बॉलीवुड में पहचान बनाने का सपना लेकर आने वाले हर कलाकार का सफर एक जैसा नहीं होता। कुछ को फिल्मी परिवार का सहारा मिलता है, तो कुछ हुनर और मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में जगह बनाने की कोशिश करते हैं। अभिनेत्री तारा सुतारिया का सफर भी ऐसा ही है। अभिनय के साथ संगीत और गायकी में रुचि रखने वाली तारा ने टेलीविजन से शुरुआत की और 2019 में करण जौहर की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से बड़े पर्दे पर कदम रखा। तारा का फिल्मी सफर कई अनुभवों से गुजर चुका है। उन्होंने रोमांटिक और एक्शन फिल्मों में काम किया और अपूर्वा जैसी सर्वाइवल थ्रिलर में मुख्य भूमिका निभाई। इस दौरान उन्हें फिल्मों से रिप्लेस किए जाने और इंडस्ट्री में आउटसाइडर होने की चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से बॉलीवुड डेब्यू

साल 2019 तारा सुतारिया के करियर के लिए महत्वपूर्ण रहा। इसी साल उन्होंने पुनीत मल्होत्रा के निर्देशन में बनी फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म में उनके साथ टाइगर श्रॉफ और अनन्या पांडे मुख्य भूमिकाओं में थे। तारा ने फिल्म में मिया चावला का किरदार निभाया। यह कॉलेज लाइफ, दोस्ती, प्यार और प्रतियोगिता पर आधारित कहानी थी। फिल्म को समीक्षकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन तारा के लिए यह बड़े पर्दे पर शुरुआत का अवसर था। तारा ने अपनी डेब्यू फिल्म के प्रदर्शन पर कहा था कि फिल्म को लेकर लोगों की राय अलग हो सकती है, लेकिन उनके अनुसार फिल्म ने कमाई की थी और वह इसे असफल नहीं मानती थीं। तारा ने बताया था कि 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' की शूटिंग के दौरान उन्हें दूसरी फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे। इनमें 'कबीर सिंह' और 'मरजावां' जैसी फिल्में शामिल थीं।

फिल्मों से रिप्लेस होने का अनुभव

फिल्म इंडस्ट्री में काम पाने के साथ-साथ किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बने रहना भी कलाकारों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तारा सुतारिया ने करियर के दौरान ऐसे अनुभवों का सामना किया है। जूम टीवी एंटरटेनमेंट के इंटरव्यू में तारा ने फिल्मों से रिप्लेस किए जाने के अनुभवों पर बात की है। उन्होंने बताया कि कुछ मौकों पर उन्हें फिल्मों से बाहर किए जाने की जानकारी मिली, जबकि वह उन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने की उम्मीद कर रही थीं। किसी फिल्म से जुड़े होने की उम्मीद के बाद अचानक किसी दूसरे कलाकार को अपनी जगह देखना भावनात्मक रूप से मुश्किल हो सकता है। तारा के लिए भी यह शुरुआती करियर का ऐसा अनुभव रहा, जिसने उन्हें इंडस्ट्री के काम करने के तरीके को समझने का अवसर दिया।

आउटसाइडर होने पर बोलीं तारा

तारा सुतारिया ने इंटरव्यू में बॉलीवुड में अपने आठ साल के सफर पर बात की थी। इस इंटरव्यू में तारा ने कहा कि जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत की, तब वह बहुत कम लोगों को जानती थीं। फिल्मी दुनिया के काम करने के तरीकों को समझने में उन्हें कई साल लगे। उन्होंने बताया था कि फिल्मी परिवार से नहीं आने वाले कलाकारों के लिए इंडस्ट्री को समझना अलग अनुभव होता है। फिल्मी परिवारों से जुड़े लोगों को कई बार फिल्मों के बनने, प्रोजेक्ट्स के ट्रैक होने और इंडस्ट्री में काम के अवसरों की जानकारी पहले से मिल जाती है। तारा के मुताबिक, बाहर से आने वाले कलाकारों के लिए ऐसी जानकारियां आसानी से उपलब्ध नहीं होतीं। उन्होंने अपने अनुभव को मुश्किल और कई बार अकेलेपन भरा बताया। हालांकि, उन्होंने कहा कि उनके माता-पिता और दोस्तों का सहयोग उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। वह अपने परिवार से काम और निजी जीवन से जुड़ी परेशानियों पर बात कर पाती हैं। तारा ने इस बातचीत में बताया कि समय के साथ उन्होंने अपनी पसंद और नापसंद को समझा। अब वह जानती हैं कि किन लोगों के साथ काम करना चाहती हैं और किस तरह के प्रोजेक्ट्स उनके लिए सही हैं।



क्या ललित मोदी का किरदार निभाएंगे रणवीर सिंह?

फिल्ममेकर साजिद नाडियाडवाला ललित मोदी की जिंदगी पर एक बड़े बजट की बायोपिक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म का निर्माण उनके बैनर नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के तहत किया जाएगा।

ललित मोदी की जिंदगी के कई पहलुओं पर होगी नजर

फिलहाल यह फिल्म लेखन और डेवलपमेंट स्टेज में है। फिल्म की कहानी, स्टारकास्ट, डायरेक्टर और रिलीज डेट को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स फिल्म में ललित मोदी की जिंदगी को सिर्फ विवादों तक सीमित नहीं रखना चाहते। कहानी में उनके निजी जीवन के साथ-साथ उनके प्रोफेशनल सफर को भी दिखाया जाएगा। फिल्म के जरिए ब्लैक के पीछे की सोच और उसे खड़ा करने में ललित मोदी की भूमिका पर भी फोकस किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि मेकर्स स्क्रिप्ट पर काफी समय दे रहे हैं, ताकि ललित मोदी की पूरी कहानी को विस्तार से पर्दे पर उतारा जा सके। लेखिका और प्रोड्यूसर स्नेहा राजानी के भी इस बायोपिक के डेवलपमेंट से जुड़े होने की खबर है। खास बात यह है कि जब ललित मोदी ने पहली बार अपनी जिंदगी पर फिल्म बनने की जानकारी दी थी, तब स्नेहा राजानी ही इस प्रोजेक्ट से जुड़ी टीम का नेतृत्व कर रही थीं। ऐसे में माना जा रहा है कि वह शुरुआत से ही इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रही हैं।

अब सबसे बड़ा सवाल फिल्म की कास्ट को लेकर है। कुछ साल पहले रणवीर सिंह ने लंदन में एक मुलाकात के दौरान ललित मोदी का किरदार पर्दे पर निभाने में दिलचस्पी दिखाई थी। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि रणवीर सिंह को इस बायोपिक के लिए फाइनल किया गया है या नहीं। ललित मोदी ने जून में भी अपनी जिंदगी पर बन रही बायोपिक को लेकर जानकारी साझा की थी। ऐसे में अब इस प्रोजेक्ट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

पोस्टपोन हो सकती है प्रभास स्टारर 'फौजी' की रिलीज डेट

प्रभास की आने वाली फिल्म 'फौजी' इन दिनों चर्चा में है। हनु राघवपुड़ी के निर्देशन में बन रही यह फिल्म एक पीरियड एक्शन ड्रामा है। अब खबर है कि फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक... 'निर्माता फिल्म को फरवरी 2027 में रिलीज करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक रिलीज की नई डेट की घोषणा नहीं हुई है। 'फौजी' की रिलीज आगे बढ़ाने की एक बड़ी वजह फिल्म का लंबा पोस्ट प्रोडक्शन काम बताया जा रहा है। फिल्म का काफी हिस्सा तैयार हो चुका है, लेकिन अभी कुछ हिस्सों की शूटिंग भी बाकी है। प्रभास जल्द ही अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर सकते हैं।

फिल्म में प्रभास के साथ इमानवी भी लीड रोल में हैं

'फौजी' में प्रभास के साथ इमानवी भी लीड रोल में नजर आएंगी। यह उनके लिए खास प्रोजेक्ट है, क्योंकि वह इस फिल्म के जरिए बड़े परदे पर लीड एक्ट्रेस के तौर पर अपनी शुरुआत कर रही हैं।

अगले प्रोजेक्ट में संजय लीला भंसाली के साथ काम कर सकते हैं महेश बाबू



तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार महेश बाबू इन दिनों निर्देशक एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग में बिजी हैं। इसी बीच उनके अगले प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक... 'महेश अब मशहूर फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ काम कर सकते हैं। दोनों के बीच एक फिल्म को लेकर बातचीत होने की खबर सामने आई है। अगर यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, तो हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक और तेलुगु सिनेमा के बड़े एक्टर पहली बार एक साथ काम करते नजर आ सकते हैं। भंसाली इस फिल्म को बड़े स्तर पर बनाने की योजना पर विचार कर रहे हैं। फिल्म में भव्य सेट, बड़े दृश्य और नाटकीय कहानी देखने को मिल सकती है।

द रेवोल्यूशनरीज के लिए रोहित सराफ ने 15 महीने की कड़ी ट्रेनिंग की



अभिनेता रोहित सराफ अपनी नई वेब सीरीज 'द रेवोल्यूशनरीज' को लेकर चर्चा में हैं। इस सीरीज में वह स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्रनाथ सान्याल का किरदार निभा रहे हैं। इस किरदार के लिए रोहित ने अपने शरीर को बदलने के लिए करीब 15 महीने तक कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग की। इसके अलावा उन्होंने लगभग 3 महीने तक मल्लखंब और कुश्ती जैसी कलाओं की ट्रेनिंग भी ली। रोहित ने बताया कि जब वह पहली बार निर्देशक निखिल आडवाणी से मिले, तो उन्होंने रोहित से कहा था कि उनका शरीर हॉलीवुड अभिनेता ब्रैड पिट जैसा होना चाहिए, जैसा कि फिल्म फाइट क्लब में दिखता है। रोहित ने कहा, 'मैं पहले से एक्टिव और फिट था, लेकिन मैं फाइट क्लब वाले ब्रैड पिट जैसा बिल्कुल नहीं था।' इसलिए उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने शरीर को निर्देशक की कल्पना के मुताबिक बनाना थी। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग काफी कठिन और थकाने वाली थी। वह अपनी ट्रेनिंग के वीडियो लगातार निखिल आडवाणी को भेजते थे। रोहित को सबसे ज्यादा अच्छा यह देखकर लगा कि धीरे-धीरे ट्रेनिंग की वजह से उनके शरीर का लुक और चलने-फिरने का तरीका दोनों बदल रहे थे।

आज यूपी कर्फ्यू, दंगा, भय, गुंडागर्दी और अवैध कब्जे से मुक्त : मुख्यमंत्री योगी

गोरखपुर, संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में ऐसी स्थिति थी कि कहावत चल पड़ी थी, 'देख सपाई, बिटिया घबराई।' अभिभावक बेटियों की पढ़ाई और सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे। तत्कालीन सरकार के गुंडों ने माहौल खराब कर रखा था। कई जिलों में बेटियों की पढ़ाई संकट में थी। सपा के शोहदे उन्हें परेशान करते थे, जबरन उठा ले जाते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी, जमीन पर कब्जे और अराजकता का माहौल था। जबकि आज उत्तर प्रदेश कर्फ्यू, दंगा, भय, गुंडागर्दी और अवैध कब्जे से मुक्त है। 2017 के बाद समाज और सरकार ने एक दिशा में काम किया तो इसके परिणाम सामने आए हैं। सीएम योगी बुधवार को चरगांवा में कृषि विभाग के बीज गोदाम के समीप



राजकीय महिला शरणालय के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। 100 महिलाओं की क्षमता वाले सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त इस भवन के निर्माण पर 8 करोड़ 5 लाख 42 हजार रुपये की लागत आई है। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि घर छोड़ने को मजबूर किसी बेटी या घरेलू हिंसा की शिकार महिला को अब दर-दर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। गोरखपुर में 100 बेड का राजकीय महिला शरणालय ऐसी महिलाओं का संबल बनेगा। आधी आबादी को सम्मान और सुरक्षा देने के साथ स्वावलंबन के पथ पर आगे बढ़ाकर विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई, विवाह, सुरक्षा और स्वावलंबन तक सरकार उसके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत जन्म से स्नातक तक बेटी के लिए 25 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में एक लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1.60 करोड़ बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, किताब, जूते-मोजे और स्वेटर की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 1.10 करोड़ परिवारों को सालाना 12 हजार रुपये पेंशन और प्रदेश में 65 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे लोगों को चुनने से अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों को सरकार चार हजार रुपये प्रतिमाह सहायता दे रही है। ऐसे बच्चों को पढ़ाई में मदद के लिए लैपटॉप भी उपलब्ध कराए गए हैं। सीएम योगी ने रोजगार को लेकर विपक्ष, खासकर सपा पर निशाना साधते हुए कहा, 'आप गिनते जाइए, हम नौकरी बांटते जाएंगे। आप गिनते-गिनते थक जाएंगे, हम यूपी के नौजवानों को नौकरी देते-देते नहीं थकेंगे।' मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन रोजगार के तहत अब तक साढ़े नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। अलग-अलग क्षेत्रों में रोजगार की नई संभावनाएं बन रही हैं। प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से तीन करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। इनमें बड़ी संख्या में इकाइयों का संचालन महिलाएं कर रही हैं। 24 हजार से अधिक स्टार्टअप के साथ उत्तर प्रदेश का युवा अब नौकरी लेने वाला ही नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला भी बन रहा है। सीएम योगी ने कहा कि लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी के रूप में महिलाएं स्वावलंबन की नई कहानी लिख रही हैं।

नारी वंदन अधिनियम के जरिए लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं के प्रतिनिधित्व का रास्ता सुनिश्चित किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 से पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस बच्चों को निगल जाती थी। अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में करीब 500 बच्चों की मौत होती थी। सरकार के प्रयासों से आज मौत का आंकड़ा शून्य पर पहुंच गया है।

आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा परंपरा का हिस्सा : ब्रजेश पाठक

लखनऊ । आयुर्वेद दिवस के अवसर पर बुधवार को लखनऊ के 1090 चौराहे से 'स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद' विषय पर बाइक रैली का आयोजन किया गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक व आयुष, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. दयाशंकर मिश्र 'दयालु' ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली 1090 चौराहे से प्रारंभ होकर जनेश्वर मिश्र पार्क तक गई। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आयुर्वेद भारत की समृद्ध एवं प्राचीन चिकित्सा परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा स्वस्थ एवं निरोगी जीवन की आधारशिला है। आयुर्वेद हमारी जीवनशैली से जुड़ा हुआ है और इसका महत्व वर्तमान समय में भी उतना ही प्रासंगिक है।उन्होंने कहा कि आज की जीवनशैली में लोग कई बार तत्काल राहत के लिए दवाओं का सहारा लेते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की उपयोगिता को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद की स्वीकार्यता आज भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व के अनेक देशों में भी इसके प्रति रुचि बढ़ी है।श्री पाठक ने कहा कि हमारी रसोई



में उपयोग होने वाले अनेक पारंपरिक मसाले एवं खाद्य पदार्थ भी भारतीय पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति से जुड़े हुए हैं। इसलिए आयुर्वेद को जन-जन तक पहुंचाने की शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार और आसपास के लोगों से करनी चाहिए। उन्होंने आह्वान किया कि आयुर्वेद को जन-जन तक पहुंचाकर स्वस्थ भारत और सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने में सभी अपनी भूमिका निभाएं। आयुर्वेद सिर्फ उपचार नहीं, स्वस्थ जीवन की पद्धति : दयाशंकर मिश्र 'दयालु'इस अवसर पर आयुष, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. दयाशंकर मिश्र 'दयालु' ने कहा कि आयुर्वेद केवल उपचार की पद्धति नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की एक समग्र जीवन पद्धति है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद कोई नई चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह सदियों से भारतीय जीवन परंपरा का हिस्सा रहा है और समाज इसका विभिन्न रूपों में प्रयोग करता आया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को संस्थागत रूप से आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं।

कूटरचित दस्तावेज से दूसरे की जमीन का बैनामा कर 18 लाख हड़पे, दो गिरफ्तार

लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी थाना पुलिस ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने दूसरे व्यक्ति की जमीन को अपना बताकर महिला और उसके पुत्र के नाम बैनामा कर दिया और इसके बदले 18 लाख रुपये ले लिए। दाखिल-खारिज नहीं होने पर महिला ने रकम वापस मांगी तो आरोपियों की ओर से दिए गए चेक भी बाउंस हो गए। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।पुलिस के मुताबिक 8 जुलाई 2026 को मंजूलता ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में शिकायत दी थी कि वह लखनऊ और आसपास आवासीय प्लॉट खरीदने के लिए जमीन तलाश रही थीं। इसी दौरान भानुप्रताप सिंह और जयप्रकाश सिंह ने कथित तौर पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर किसी अन्य व्यक्ति की जमीन का बैनामा उनके और उनके पुत्र के नाम कर दिया। इसके एवज में उनसे कुल 18 लाख रुपये लिए गए। बाद में जमीन का दाखिल-खारिज नहीं होने पर उन्होंने आरोपियों से अपनी धनराशि वापस मांगी। आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें चेक दिए, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गए। शिकायतकर्ता ने दोनों पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया।शिकायत के आधार पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा संख्या 430/2026 के तहत धारा 318(4), 338, 336(3), 352, 351(3) और 3(5) बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देशन में दो पुलिस टीमों का गठन किया गया। टीमों ने तकनीकी और मैनुअल साक्ष्यों तथा स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जयप्रकाश सिंह पुत्र अनंत बहादुर सिंह, निवासी ग्राम टोडरपुर, थाना मोहनगंज, अमेठी, वर्तमान पता सेक्टर-1, वरदानखंड, थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ तथा भानुप्रताप सिंह उर्फ बच्चन सिंह पुत्र शिवप्रताप सिंह, निवासी पूरने बलवंत सिंह, पोस्ट रहवा, थाना हरचंदपुर, रायबरेली के रूप में हुई है।पुलिस पूछताछ में जयप्रकाश सिंह ने बताया कि वह और उसका जीजा भानुप्रताप सिंह उर्फ बच्चन सिंह जमीन की खरीद-फरोख्त का काम करते हैं।

राज्यपाल ने 'सेवा संकल्प अभियान-2026' के अंतर्गत आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया शुभारंभ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने जन भवन में 'सेवा संकल्प अभियान-2026' (17 सितम्बर से 17 अक्टूबर, 2026) के अंतर्गत किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग द्वारा आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जन भवन में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक स्वैच्छिक रक्तदान किया। शिविर में कुल 39 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। राज्यपाल ने रक्तदान करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों से भेंट की तथा उनके इस मानवीय एवं सेवाभावी कार्य की सराहना करते हुए उन्हें एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने रक्तदाताओं से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया।



'सेवा संकल्प अभियान-2026' के अंतर्गत आयोजित इस शिविर का उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करना तथा जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहयोग प्रदान करना है। इस प्रकार के सेवा-आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समाजहित एवं मानव सेवा के कार्यों में सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी (अपर मुख्य सचिव स्तर) डॉ. सुधीर महादेव बोबडे, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी तथा जन भवन के अधिकारी एवं कर्मचारी

विद्यार्थियों ने किया अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन

विद्यार्थी तनावमुत शिक्षा के साथ सफल जीवन का लक्ष्य बनायें : पंकज तिवारी



लखनऊ। जनविकास महासभा एवं सोक्ट द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे विद्यार्थी प्रतिभा उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज सिटी पब्लिक हाई स्कूल, 60 फिट रोड,जानकीपुरम में विद्यार्थियों द्वारा नृत्य, गायन, संगीत, स्पीच इत्यादि प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर उन्हें प्रतिभा के प्रदर्शन के प्रति प्रोत्साहित करते हुये तनाव मुक्त शिक्षा और सफल जीवन के बारे में बताया गया। इस मौके पर जनविकास महासभा के अध्यक्ष पंकज तिवारी, महामंत्री व परी पुस्तक केंद्र के प्रमुख अजय यादव, स्कूल संस्थापक प्रबन्धक आशा गुप्ता, प्रधानाचार्या दीप्ति गुप्ता, उप प्रधानाचार्या वैशाली सिन्हा, कोआर्डिनेटर अंकिता पाण्डेय, अध्यापिकाओं में महक तिवारी, दीपिका मिश्रा व साधना यादव आदि प्रमुख लोग मौजूद थे। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए पंकज तिवारी ने विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज के विद्यार्थी कल के राष्ट्र निर्माता होंगे, अतः विद्यार्थियों को अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की जिम्मेदारियां के प्रति जागरूक रहते हुए अपने स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं जल संरक्षण तथा नशा मुक्त समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। अतः उन्हें तनाव मुक्त शिक्षा एवं सफल जीवन जीने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना होगा इसके लिए उन्हें अपनी प्रतिभा के प्रति भी जागरूक होना होगाक्योंकि जो विद्यार्थी अपने टैलेंट के अनुरूप अपना करियर का चुनाव करते हैं उनके जीवन में सफल होने का प्रतिशत ज्यादा होता है।

ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए: संजय सिंह

लखनऊ। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, फॉर्म-6 में किए गए गैर-कानूनी बदलावों और देश की कानून-व्यवस्था को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। बुधवार को सोशल मीडिया के माध्यम से बयान जारी करते हुए सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश में लोकतंत्र पूरी तरह खतरे में है। चुनाव आयोग के अंदर दो चुनाव आयुक्तों ने 14 बार असहमति दर्ज कराते हुए फॉर्म-6 में बदलाव और वोटों के जोड़ने-घटाने की केंद्रीकृत व्यवस्था को गैर-कानूनी बताया, लेकिन इसके बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तानाशाही रवैया अपनाते हुए एकतरफा फैसले ले रहे हैं। सांसद संजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा वोटों को डिलीट करने और जोड़ने का जो नया केंद्रीकृत फॉर्मूला लागू किया गया है, उस पर खुद दो चुनाव आयुक्तों ने 14 बार लिखित विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने साफ कहा था कि आपका यह तरीका गलत है और राज्यों के स्थानीय अधिकारियों (एसडीएम आदि) से अधिकार छीनकर मनमाने ढंग से नाम काटना पूरी तरह असंवैधानिक है। संजय सिंह ने कहा कि जब आयोग के अंदर ही दो आयुक्त इसे गलत बता रहे हैं, तो ज्ञानेश कुमार किसके इशारे पर यह मनमानी कर रहे हैं? आज किसी भी विधानसभा में 50,000 वोट काट दिए जाते हैं और भाजपा 5,000 वोटों से जीतकर अपनी जीत का ढोल पीटने लगती है। यह



कोई चुनाव नहीं, बल्कि मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार की मिलीभगत से की जा रही वोटों की खुली लूट है। संजय सिंह ने कहा कि यह नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता नहीं, बल्कि उनकी श्लूटप्रियताश् है जिसके दम पर चुनाव जीते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फॉर्म-6 के नियमों को जानबूझकर इतना जटिल बनाया गया है ताकि आम नागरिक इसे पूरा ही न कर सके। बंगाल में 60 लाख नाम काट दिए गए, 27 लाख नाम पेंडिंग रखे गए और बाद में हलफनामा देकर माना कि 93 फीसदी नाम बिल्कुल सही थे। उन्होंने सवाल किया कि जिन लाखों वैध नागरिकों को मताधिकार से वंचित किया गया, उस अपराध के लिए जेल कौन जाएगा? उन्होंने कहा कि दिल्ली में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व सेना प्रमुख, विदेश मंत्री, विदेश सचिव, तीन बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उनके परिवार, मनीष सिसोदिया और कपिल सिब्बल तक के नाम काट दिए गए। यहां तक कि चुनाव आयुक्त संधू का नाम भी लिस्ट से गायब कर दिया गया। जब देश के शीर्ष पदों पर रहे लोगों के साथ यह हो सकता है, तो आम जनता के मताधिकार की क्या बिसात? आप सांसद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में आंख पर पट्टी बांधकर श्धृतराष्ट्रश् की भूमिका निभा रहा है। जब 93 फीसदी वोटर्स सही पाए गए थे, तो उन्हें वोट देने से क्यों रोका गया? संजय सिंह ने दो टूक मांग की कि ज्ञानेश कुमार के पद पर रहते हुए देश में कभी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, इसलिए उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर जेल में डाला जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि धांधली और वोट कटाई की आड़ में कराए गए बिहार, बंगाल, दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत तमाम राज्यों के चुनाव रद्द किए जाएं और निष्पक्ष मतदाता सूची के साथ दोबारा चुनाव कराए जाएं।

संक्षिप्त समाचार

व्हाट्सऐप पर 'नो' लिखते ही खाते से निकल गए 1.70 लाख रुपये

लखनऊ। साइबर ठगों ने बैंक खातों से रकम उड़ाने का एक नया तरीका अपनाया है, जिसमें पीड़ित को किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने या एक बार इस्तेमाल होने वाला पासवर्ड साझा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठग व्हाट्सऐप के जरिए ऐसा संदेश भेजते हैं, जिसमें खाते से बड़ी रकम निकलने की जानकारी दी जाती है और लेनदेन नहीं करने पर 'नो' लिखकर जवाब देने को कहा जाता है। बताया जा रहा है कि जवाब देते ही मोबाइल में मौजूद एक छिपी हुई स्वचालित प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है, जिसके जरिए ठग मोबाइल तक पहुंच बनाने का प्रयास करते हैं।सामने आए एक मामले में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक खातों से करीब 1.70 लाख रुपये निकल गए। पीड़ित के अनुसार उन्होंने किसी लिंक पर क्लिक नहीं किया था और न ही किसी को एक बार इस्तेमाल होने वाला पासवर्ड बताया था। उन्हें पहले व्हाट्सऐप पर खाते से करीब 90 हजार रुपये डेबिट होने का संदेश मिला। इसके कुछ ही देर बाद दूसरा संदेश आया, जिसमें पूछा गया कि यदि यह लेनदेन उन्होंने नहीं किया है तो 'नो' लिखकर जवाब दें। पीड़ित ने निर्देश के अनुसार जवाब दिया और इसके बाद उनके बैंक खातों से रकम निकल गई।साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के संदेशों का उद्देश्य लोगों में घबराहट पैदा कर उनसे तत्काल प्रतिक्रिया करवाना होता है। संदेश में छिपी संदिग्ध फाइल या अन्य तकनीकी माध्यम के जरिए मोबाइल तक अनधिकृत पहुंच बनाने का प्रयास किया जा सकता है। हालांकि, किसी संदेश का जवाब देना अपने आप में हर स्थिति में मोबाइल का पूरा नियंत्रण ठगों को दे देता है, ऐसा सामान्य रूप से नहीं माना जा सकता; ठगी का तरीका इस्तेमाल किए गए उपकरण, फाइल, अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है।ऐसे मामलों से बचने के लिए अनजान नंबर से बैंक खाते में लेनदेन संबंधी कोई संदेश आने पर उसका जवाब नहीं देना चाहिए। संदेश में दिए किसी नंबर, लिंक या निर्देश के आधार पर कार्रवाई करने के बजाय बैंक के आधिकारिक अनुप्रयोग या बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से खाते का विवरण और शेष राशि जांचनी चाहिए। बैंक से संपर्क करने के लिए केवल बैंक के आधिकारिक ग्राहक सेवा माध्यमों का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी संदिग्ध फाइल को खोलने या मोबाइल में अनावश्यक अनुमति देने से बचना चाहिए। यदि खाते से अनधिकृत रकम निकल जाए तो तत्काल बैंक को सूचित कर खाते को सुरक्षित कराने के साथ साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए।

कर्मचारी नेता का निधन

लखनऊ । उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के संरक्षक एवं उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्र प्रताप सिंह का हृदय गति रुकने से देर रात निधन हो गया। बुधवार को इंदिरा नगर स्थित उनके निवास से शवयात्रा बैकुण्ठ धाम पहुंची। सुबह 11 बजे गोमती नदी किनारे बैकुण्ठ धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। चिता को मुखाग्नि उनके पुत्र कुशम्बु सिंह ने दी। अंतिम संस्कार में अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसपी सिंह, अमरनाथ यादव, बीएल कुशवाह, ओपी त्रिपाठी, अंगद सिंह, कमलेश मिश्रा, हेमंत गूजर, अशोक सिंह, परमेश्वर सिंह, परवेज खान, अफीफ सिद्दीकी, धर्मेंद्र सिंह, श्याम सिंह, संदीप पांडे, मंसूर अली, देवेंद्र यादव, शैलेंद्र यादव और पवन द्विवेदी सहित सैकड़ों सेवानिवृत्त व सेवारत कर्मचारी मौजूद रहे।

बारिश' लेकर आएगी लखनऊ में संगीत लोककला और तहजीब का रंग

लखनऊ । मानसून की विदाई के साथ ही लखनऊ में एक ऐसी शाम सजने जा रही है, जो बारिश को महज एक मौसम नहीं, बल्कि संगीत, कला, किस्सागोई, शिल्प, स्वाद, खुशबू और सांस्कृतिक स्मृतियों के जीवंत उत्सव के रूप में सामने लाएगी। 'बारिश दृ आर्ट।म्यूजिक।मानसून।' शनिवार, 26 सितंबर 2026 को होटल क्लार्क्स अवध, लखनऊ में अपने रंग बिखेरेगी।एक्सक्यूरेटर्स इवेंट्स द्वारा क्यूरेट एवं निर्मित यह विशेष शाम सावन की सांस्कृतिक विरासत और लखनऊ की तहजीब को एक अनूठे अनुभव में पिरोएगी। शाम की शुरुआत अस्करी नकवी की भावपूर्ण और सूफियाना संगीत प्रस्तुति से होगी। इसके बाद चर्चित कवि तथा संगीत एवं सिनेमा के अध्येता यतीन्द्र मिश्र अपनी प्रस्तुति के माध्यम से संगीत, साहित्य और सिनेमा के विविध रंगों से रूबरू कराएंगे। शाम को अपनी ऊर्जावान प्रस्तुति से द कुटले खान प्रोजेक्ट आगे बढ़ाएगा, जो दर्शकों को लोक और सूफी संगीत की समृद्ध परंपराओं की जीवंत यात्रा पर ले जाएगा।कार्यक्रम का संचालन वाराणसी के सौरभ चक्रवर्ती करेंगे, जो प्रस्तुतियों, संवादों और शाम से जुड़े विभिन्न अनुभवों को एक सूत्र में पिरोते हुए इस सांस्कृतिक उत्सव को आगे बढ़ाएंगे। लखनऊ में 'बारिश' का अनुभव संगीत और प्रस्तुतियों से आगे बढ़ते हुए सांस्कृतिक संवादों, 'बारिश बाजार', हस्तशिल्प, चुनिंदा खान-पान एवं पेय और विविध अनुभवात्मक गतिविधियों के माध्यम से जीवंत होगा। यह आयोजन लखनऊ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, उसकी तहजीब और जीवन के विविध रंगों को एक साझा मंच पर प्रस्तुत करेगा। दर्शकों को बारिश से जुड़ी स्मृतियों, भावनाओं, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के विभिन्न रूपों से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। इन सभी अनुभवों के माध्यम से 'बारिश' सावन की बदलती मनोदशाओं और लखनऊ की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को एक साथ पिरोते हुए ऐसी शाम रचेगी, जिसे दर्शक केवल देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि महसूस भी करेंगे।मानसून का बहु-शहरी उत्सव 'बारिश' दिल्ली से देश के विभिन्न शहरों तक अपनी यात्रा के दौरान भारत की साझा और समन्वयी संस्कृति में बारिश की विविध अभिव्यक्तियों को तलाशता आया है। दिल्ली के सफल अध्यायों और जयपुर संस्करण के बाद अब 'बारिश' लखनऊ पहुंच रही हैकृएक ऐसे शहर में, जिसकी सांस्कृतिक पहचान मेहमाननवाजी, संगीत, शायरी, खान-पान, शिल्प और तहजीब की समृद्ध परंपराओं से गहराई से जुड़ी है। लखनऊ में 'बारिश' इसी सांस्कृतिक विरासत के विभिन्न रंगों को बारिश से जुड़ी स्मृतियों, भावनाओं और परंपराओं के साथ जोड़ते हुए एक अनूठा अनुभव प्रस्तुत करेगी।

कान्हा गौशाला नवीन मंडी में आचार्य श्री विद्यासागर जीव दया ट्रस्ट ने की गौ सेवा

रिपोर्टर पारस बंसल शामली

शामली। आचार्य श्री विद्यासागर जीव दया ट्रस्ट रजि., शामली के तत्वावधान में रविवार को नवीन मंडी स्थित गौशाला में गौ सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेवा कार्य अमित जैन एवं उनके पारिवारिक जैन परिवार के सौजन्य से संपन्न हुआ। इस अवसर पर ट्रस्ट अध्यक्ष अमित जैन ने कहा कि जीव मात्र के प्रति करुणा और सेवा का भाव भारतीय संस्कृति एवं जैन दर्शन की महत्वपूर्ण विशेषता है। गौ सेवा के माध्यम से समाज में जीव दया और सेवा की भावना को बढ़ावा मिलता है। कार्यक्रम में ट्रस्ट के मंत्री अंशु जैन, कोषाध्यक्ष मनीष जैन, संयोजक अरिहंत जैन, उपाध्यक्ष संजय जैन, पीयूष जैन, नमी जैन, अरिहंत जैन, प्रिंस जैन, सिद्धार्थ जैन, मानविक जैन सहित अन्य सदस्य एवं सहयोगी उपस्थित रहे। ट्रस्ट पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था द्वारा जीव दया, गौ सेवा एवं जरूरतमंद जीवों की सहायता के लिए निरंतर सेवा कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने समाज के लोगों से भी ऐसे पुनीत कार्यों में बढ़-चढ़कर सहयोग करने का आह्वान किया।



जीव दया और गौ सेवा भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर — **अमित जैन, अध्यक्ष**

डॉ. शक्ति सिंह साधू (प्रधान सम्पादक), डॉ. प्रवीण (प्रबंध सम्पादक), एडवोकेट शैलेन्द्र श्रीवास्तव (कानूनी सलाहकार), राकेश अग्रवाल (जिला ब्यूरो उत्तर प्रदेश) अब्दुल नासिर स्टेट ब्यूरो उत्तर प्रदेश

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक शक्ति सिंह द्वारा राज तरूण आफसेट, एल0जी0एफ0 5–14, अंसल सिटी सेंटर, हजरतगंज, लखनऊ– 226001 से मुद्रित तथा 486/238–डी, डालीगंज, निरालानगर, जनपद लखनऊ–226020 से प्रकाशित।

सम्पादक– शक्ति सिंह मो0 7052608007 नोटः समाचार पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ न्यायालय होगा।